Achievers IAS Academy

Hindu Summary

07/04/2023

हिंदू 07-04-2023

राष्ट्रीय

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को पीआईबी द्वारा चिह्नित 'फर्जी समाचार' पर कार्रवाई करनी चाहिए

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर अन्य बिचौलियों को अब यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार के बारे में "फर्जी समाचार" लेख, उनके पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा माने और घोषित किए गए हैं, उनके प्लेटफार्मों से हटा दिए जाते हैं; जब उन्हें ऐसी पोस्ट के लिए अलर्ट किया जाता है।

गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता), संशोधन नियम 2023, आईटी नियम 2021 में संशोधन के माध्यम से परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया।

आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री। राजीव चंद्रशेखरन ने किसी भी दावे को खारिज कर दिया कि यह प्रेस को सेंसर करेगा।

पीआईबी → फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नियुक्ति की गई है।

ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग चेक करने के लिए संशोधन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने गुरुवार को "ऑनलाइन रियल मनी गेम्स" को विनियमित करने के लिए आईटी नियम 2021 का एक संशोधन जारी किया, जहां उपयोगकर्ताओं को खेलने के लिए पैसे का जोखिम उठाना पड़ता है।

नए आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) संशोधन नियम, 2023. सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड (एसआरबी) के साथ रजिस्टर करने के लिए रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है।

एसआरबी पहचानेंगे कि गेम "अनुमत" हैं या नहीं। तीन SRBS जल्द ही और अधिक पहचाने जाएंगे। एसआरबी कैसे काम करते हैं, इस पर अब और निगरानी होगी। यदि खेलों को "अनुमेय" नहीं माना जाता है तो उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी और राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। हालांकि, जिन लोगों को अनुमति दी गई है उन्हें कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वे जीत की उम्मीद के खिलाफ जमा राशि शामिल करते हों।

वीडियो गेम जिसमें पैसा शामिल नहीं है, एसआरबी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, प्लेटफार्मों और ऑनलाइन मध्यस्थों को एक नई सलाह चेतावनी जारी की है। सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रसारित करने के खिलाफ। समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन समाचार प्रकाशकों सहित सभी मीडिया प्रारूपों को सलाह जारी की गई है

ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन

↓

सूचान प्रौद्योगिकी

(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023

MeITY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(स्व नियामक (SRB) MeiTy के तहत गठित

अगर पैसा गेमिंग प्लेटफॉर्म में शामिल है

↓ ↓

एसआरबी द्वारा क्लियर किया गया एसआरबी द्वारा क्लियर नहीं किया गया

↘

एसआरबी द्वारा विनियमित कार्रवाई प्रतिबंध का सामना करेंगे

आरबीआई के 6.5% पर नीतिगत दर रखने के बाद दास कहते हैं, ठहराव धुरी नहीं है

गुरुवार को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता का हवाला देते हुए वैश्विक वित्तीय स्थिरता का हवाला देते हुए 6 में से पांच सदस्यों ने विकास का समर्थन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो, समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मतदान किया।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'यह धुरी नहीं विराम है'

"हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मुद्रास्फीति के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि हम मुद्रास्फीति में टिकाऊ गिरावट को लक्ष्य के करीब न देख लें। हम उचित और समय पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं"

पॉलिसी रेट में पिछले एक साल में 290 बीपीएस की बढ़ोतरी हुई है।

यह मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किया गया था।

Mpc → RBI की मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों में वृद्धि या कमी का निर्णय लेती है।

नीतिगत दर → रेपो दर ब्याज दर जिस पर बैंक पैसे ले सकते हैं

गृह मंत्रालय ने एफसीआरए उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की।

ऑक्सफैम →

यह यूके स्थित एक एनजीओ है जो असमानता में कमी के क्षेत्र में काम करता है; गरीबी में कमी आदि। ऑक्सफैम की शाखाएं भारत में भी हैं

विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम (FCRA) → भारत में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण FCRA के तहत विनियमित किया जाता है। यदि कोई निकाय एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है, तो वह विदेशी कंपनियों, व्यक्तियों आदि से धन प्राप्त नहीं कर सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ऑक्सफैम इंडिया द्वारा एफसीआरए प्रावधानों के कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की।
एफसीआरए संशोधन अधिनियम 2020 के तहत, भारत में काम करने वाला एक एनजीओ विदेशी धन को अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। हालांकि, ऑक्सफैम इंडिया को इसका उल्लंघन करते पाया गया। इसका एफसीआरए लाइसेंस दिसंबर, 2021 को रद्द कर दिया गया था। इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है।

7 सितंबर, 2022 को आयकर विभाग ने ऑक्सफैम इंडियन और सीपीआर (नीति अनुसंधान केंद्र) के कार्यालयों की तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पाया कि ऑक्सफैम इंडिया अपना फंड अन्य एफसीआरए पंजीकृत संघों को भेजने की कोशिश कर रहा था। इसने अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से आयोग के रूप में अपने फंड को सीपीआर में स्थानांतरित कर दिया।

ऑक्सफैम इंडिया ने एक बयान में कहा कि उन्हें भारतीय कानूनों से पूरी तरह शिकायत है। उन्होंने दिसंबर: 2021 निलंबन के बाद अपने एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकृत नहीं करने के केंद्र के फैसले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है।

अंतरिक्ष नीति के लिए सरकार की मंजूरी निजी खिलाड़ी को मिलेगी

सरकार ने गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी, जो इसरो के अनुसंधान और विकास और उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीति निजी क्षेत्र को एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगी जिसमें उपग्रह, रॉकेट और लॉन्च वाहन बनाना और डेटा संग्रह शामिल है। इसरो की भूमिका; इसमें NSIL को निर्दिष्ट किया गया है।

नीति अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भारी बढ़ावा देगी। उद्योग।

भारत ने पत्रकारों के अनुचित व्यवहार के चीन के आरोप का खंडन किया।

मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया था कि चीन में कार्यरत दो भारतीय पत्रकारों के वीजा 'फ्रीज' कर दिए गए हैं. चीन के विदेश मंत्रालय (एमएफए) द्वारा दिया गया कारण यह था कि चीनी पत्रकार को भारत में अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही चीनी पत्रकार को वीजा नहीं दिया गया।

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA)

दुनिया

मैक्रोन ने चीन के शी को यूक्रेन में शांति के लिए रूस के साथ तर्क करने के लिए कहा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन और यूरोपीय संघ (ईयू) के राष्ट्रपति वेंडर (उर्सुला वान डेर लेयेन) की चीन की यात्रा पर।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को चीन के शी जिनपिंग से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया।

यूक्रेन में रूसी आक्रमण ने लोगों के ग्रेट हॉल में शी जिनपिंग के साथ-साथ खड़े [अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता" को झटका दिया है। तालिका" चीन, यूरोप व्यापार पर श्री मैक्रॉन ने कहा कि यूरोप को चीन के साथ व्यापार और कूटनीति को कम करने का विरोध करना चाहिए और जिसे किसी ने चीन और पश्चिम के बीच तनाव का "अविवेकी सर्पिल" कहा है, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए।

2019 में ईयू अध्यक्ष बनने के बाद वोंडर लेयेन की यह पहली चीन यात्रा है। दोनों नेताओं को 21 तोपों की सलामी दी गई।

लाबानोन से रॉकेट सैल्वो संघर्ष के बाद इज़राइल को निशाना बनाता है

इजराइल पर लैबोन की ओर से रॉकेटों की बौछार शुरू की गई, यह 2006 के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि है जब इजराइल और हिज़्बुल्लाह ने 34 दिनों तक लड़ाई की, क्या इजराइल की सेना ने कहा कि उसने इजराइली क्षेत्र को निकाल दिया था, 25 को इजराइली सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

यह हमला इस्राइली सुरक्षा बलों द्वारा यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद पर छापा मारने के कुछ दिनों बाद हुआ है। इसने फिलिस्तीनी से व्यापक प्रसार विरोध को आकर्षित किया था।
भारत ने गुरुवार को अल-अक्सा मस्जिद घटना के बाद सभी पक्षों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया।

अल-अक्सा मस्जिद → यह मक्का और मीडिया के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।

हिज़्बुल्लाह → यह लैबनेस शिया इस्लामवादी और मिलिटेंट समूह है
इज़राइल - हिज़्बुल्लाह युद्ध 2006 → इज़राइल द्वारा लोहबोन पर नौसेना की रुकावट डालने के बाद इज़राइल मिलिटरी और हिज़्बुल्लाह के बीच लड़ा गया। यह 34 दिनों तक लड़ा गया और बाद में संयुक्त राष्ट्र शांति संधि के तहत इसका समाधान निकाला गया।

सऊदी अरब, ईरान संयुक्त योजना पर समझौते पर पहुँचे।
ईरान और सऊदी अरब संयुक्त रूप से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ एक दूसरे के देशों में फिर से शर्मिंदगी उठाने के लिए वृद्ध हो गए हैं।
यह दोनों देशों के विदेश मंत्री की बीजिंग में मुलाकात के बाद आया है।
जापान की सेना ने कहा कि 10 लोगों को ले जा रहा हेलीकाप्टर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया

हजारों म्यांमार से भागकर सीमा पार कर रहे हैं
हजारों म्यांमार के लोग थाईलैंड भाग गए हैं क्योंकि म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई चल रही है।
लगभग 3,998 लोगों ने एसी आधिकारिक आंकड़े दर्ज किए हैं।

अमेरिका-ताइवान बैठक के बाद चीन ने जोरदार कदम उठाने का वादा किया

संपादकीय-1

खुला न्याय

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रक्रिया दोनों पर प्रहार किया है

संपादकीय किस बारे में है?

संपादकीय हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में है जिसमें इसने अपनी सामग्री प्रसारित करने के लिए मलयालम चैनल के अधिकारों को बहाल किया। SC का फैसला सरकार पर भारी पड़ा है. SC ने सीलबंद कवर दस्तावेजों का अधिक बार उपयोग करने के लिए सरकार की आलोचना की।

SC का मामला और निर्णय क्या है?

मलयालम चैनल मीडिया वन को सरकार ने इसकी सामग्री को स्थापना विरोधी बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था।

मीडिया वन केरल उच्च न्यायालय गया जिसमें प्रतिबंध के सरकार के दावे को कायम रखा गया'।

मीडिया वन अब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार से 4 सप्ताह में इस चैनल पर से प्रतिबंध हटाने को कहा है।

सरकार ने तर्क दिया है कि इसकी सामग्री राष्ट्र-विरोधी और भारत सरकार के खिलाफ है। इसने इस बात का भी सबूत दिया कि उसके शेयरधारकों का संबंध प्रतिबंधित जमामा-ए-इस्लामी से है।

SC का फैसला क्या था?

SC ने बताया कि सरकार आलोचनात्मक कवरेज या आलोचनात्मक राय को सत्ता विरोधी नहीं कह सकती है और इसलिए कार्रवाई शुरू कर सकती है।

“इस तरह की शब्दावली का उपयोग उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि सरकार। स्थापना का समर्थन करना चाहिए ”। मंजूरी से इनकार "विशेष रूप से प्रेन फ्रीडन पर मुक्त भाषण पर एक द्रुतशीतन प्रभाव पैदा करता है।"

SC ने की सरकार की आलोचना "सीलबंद कवर प्रक्रिया" पर। इसमें कहा गया है कि वास्तविक कवर में क्या है, इसके बारे में जानकारी पीड़ित पक्षों को प्रदान की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद कवर वसीयत के साथ एक नई प्रक्रिया भी विकसित की है।

संपादकीय-2

सब्स्टेंस, सबटेक्स्ट

भूटान के राजा भारत की यात्रा सहयोग बढ़ाने और आशंकाओं को दूर करने के लिए की गई थी।

संपादकीय किस बारे में है?

हाल ही में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल क्लैंग चक भारत आए थे। इस दौरे पर कई अहम फैसले लिए गए। कम करने में मदद मिली है। चीन से लगी सीमाओं पर भूटान के प्रधानमंत्री की हाल की टिप्पणी को लेकर भारत की चिंता।

भूटान नरेश की भारत यात्रा के कौन-कौन से प्रमुख समझौते हुए।

भूटान नरेश ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संयुक्त वक्तव्य में कई क्षेत्रों में विस्तृत सहयोग पर बल दिया गया है:-

भारत भूटान की अगली विकासात्मक योजनाओं का समर्थन करने और क्रेडिट पर अतिरिक्त स्टैंड बाय लाइन देने पर सहमत हो गया है

जलविद्युत, दोनों देशों के बीच संबंधों की "आधारशिला" को भी बढ़ावा मिला है। भारत सरकार ने संकोश और पुनातसांगचू जलविद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की।

चुक्का जलविद्युत बिजली के लिए शुल्क संशोधित किया गया है:
भारत बसोचू पावर प्रोजेक्ट से बिजली खरीदेगा।

नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में जयगांव में ट्रकों के लिए एक एकीकृत चेकपॉइंट, तीसरे देश के नागरिकों के लिए एक चेकपॉइंट शामिल है।
क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक b/w कोकराझार और गेल्फी की स्थापना की जाएगी।

अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में कौशल साझेदारी, कौशल अनुसंधान, स्टार्टअप और एसटीईएम